खण्ड–07 सत्र–02 अंक–09

सोमवार 08 मार्च, 2021 17 फाल्गुन, 1942 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

दूसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड–07 (भाग–1) में अंक 09 से अंक 13 सम्मिलित है।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन
सचिव
C. VELMURUGAN
Secretary

महेन्द्र गुप्ता
उप सचिव (सम्पादन)
MAHENDRA GUPTA
Deputy Secretary(Editing)

विषय–सूची

सत्र–2 (भाग–1) – सोमवार, 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) अंक–09

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	3–4
2.	निधन संबंधी उल्लेख	5–6
3.	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का सदन को सम्बोधन तथा माननीय उपाध्यक्ष महोदया को सदन का संचालन करने हेतु आमंत्रण	7–8
4.	माननीय उप–राज्यपाल का अभिभाषण (हिन्दी/अंग्रेजी)	9–27
5.	माननीय उप मुख्यमंत्री, दिल्ली द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 का प्रस्तुतीकरण	29
6.	कार्य मंत्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	29
7.	माननीय उप मुख्यमंत्री, दिल्ली द्वारा आउटकम बजट 2020–21 की 31 दिसम्बर, 2020 तक की स्टेटस रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण	29–39
8.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	40–44

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र – 2, सोमवार, 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) अंक 09

दिल्ली विधान सभा
सदन दोपहर 12:00 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए

1	श्री अजेश यादव	16	श्री करतार सिंह तंवर
2	श्री अखिलेश पति त्रिपाठी	17	श्री कुलदीप कुमार
3	श्रीमती ए धनवती चंदीला ए	18	श्री मुकेश अहलावत
4	श्री अजय दत्त	19	श्री महेन्द्र यादव
5	सुश्री आतिशी	20	श्री मदन लाल
6	श्री अभय वर्मा	21	श्री मोहन सिंह बिष्ट
7	श्री अनिल कुमार बाजपेयी	22	श्री ओमप्रकाश शर्मा
8	श्री अब्दुल रहमान	23	श्री पवन शर्मा
9	श्री अजय कुमार महावर	24	श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
10	श्रीमती बंदना कुमारी	25	श्री प्रलाद सिंह साहनी
11	श्री धर्मपाल लाकड़ा	26	श्री प्रवीण कुमार
12	श्री गिरीश सोनी	27	श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
13	श्री हाजी युनूस	28	श्री प्रकाश जारवाल
14	श्री जय भगवान	29	श्री रघुविंदर शौकीन
15	श्री जरनैल सिंह	30	श्री राजेश गुप्ता

31	श्री राज कुमार आनंद	40	श्री सोमनाथ भारती
32	श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों	41	श्री सौरभ भारद्वाज
33	श्री राजेश ऋषि	42	श्री सही राम
34	श्री राघव चड्ढ़ा	43	श्री एस के बग्गा
35	श्री रोहित कुमार	44	श्री विजेंद्र गुप्ता
36	श्री संजीव झा	45	श्री विशेष रवि
37	श्री सोम दत्त	46	श्री विनय मिश्रा
38	श्री शोएब इकबाल	47	श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
39	श्री शिव चरण गोयल		

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र–2, सोमवार, 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) अंक–09

सदन दोपहर 12.00 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद–धन्यवाद। राष्ट्रीय गीत, वन्दे मातरम्।

राष्ट्रीयगीत–वन्दे मातरम्

निधन सम्बन्धी उल्लेख

माननीय अध्यक्षः सातवीं विधान सभा के दूसरे सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको मालूम ही है कि यह बजट सत्र है। इसमें उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा करने के दौरान आपको अपने विचार प्रकट करने का पूरा मौका मिलेगा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनता से और कम से कम समय में अपनी बात कहें और सदन का समय खराब न होने दें। सदन के समय का सदुपयोग करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अतः आप सबसे मेरा पुनः अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही में नियमित रूप से तथा शालीनतापूर्वक भाग लें और कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग दें। इसके अलावा प्रत्येक बैठक अब पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगी। अतः सदस्य इस बात का ध्यान रखें और निर्धारित समय पर सदन मे पहुंचने का कष्ट करें। आप सब जानते हैं कि उतराखंड के चमौली जिले में गत 7 फरवरी, 2021 को नंदादेवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूट जाने से विकराल बाढ़ आ गई और इससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 70 से भी ज्यादा व्यक्ति मारे गये और सैंकड़ों लापता हो गये। ऋषि गंगा बिजली परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। धौली गंगा का बांध टूट गया तथा एन टी पी सी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना को बहुत नुकसान हुआ।

अनेक मकान बाढ़ में बह गये। यह अपूरणीय क्षति है और इस आपदा से निपटने में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास सराहनीय हैं। जिन लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ा, वह अत्यंत दुखद है। मैं इस आपदा में मारे गये व्यक्तियों तथा लापता व्यक्तियों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस अपार कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

आप जानते हैं कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान पिछले तीन महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। वे मौसम की खराब परिस्थितियों से लगातार जूझते हुए संघर्ष कर रहे हैं। इस कारण कई किसानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इस आंदोलन में अपनी जान की बाजी लगाने वाले किसानों के लिए हार्दिक संवेदना और सहानुभूति प्रकट करता हूं। इस मुद्दे का जितनी जल्दी समाधान हो सके, उतना ही अच्छा रहेगा। अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया गया)

ओम शांति, शांति, शांति। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गत 25 जनवरी. 2021 को विधानसभा परिसर में अशोक स्तम्भ स्थापित किया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्य अतिथि रहे और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि रहे। इस ऐतिहासिक परिसर में अशोक स्तम्भ की स्थापना निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। किसी भी सत्ता का लक्ष्य केवल राजनैतिक और सैनिक सफलता नहीं बल्कि जनहित होना चाहिए। अशोक स्तम्भ भी वास्तव में हमें यही प्रेरणा देता है कि राज सत्ता का सदुपयोग जनहित के कार्यों के लिए किया जाये। यह स्तम्भ भारतीय गणतंत्र की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब है तथा इसके साथ उत्तरदायित्व भी जुड़े हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे जन प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय पूर्ण उत्तरदायित्व का ध्यान रखेंगे। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको यह सूचित करते

हुए भी हर्ष हो रहा है कि इस सदन की अध्यक्ष दीर्घा, प्रेस दीर्घा और दर्शक दीर्घा को शीशे से कवर कर दिया गया है। यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से उठाया गया है ताकि सदन में कोई असामाजिक तत्व पर्चे, बैनर आदि फेंककर इसकी गरिमा को नष्ट न करें। जो ऊपर का ये कवर है ये सारा शीशे से कवर कर दिया गया है। माननीय सदस्य गण, जैसा आप सब जानते हैं आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला शक्ति हमारे समाज की ताकत है। जीवन का हर क्षेत्र महिलाओं के बिना अधूरा है। सदियों से समय की धार पर चलती हुई महिला शक्ति अनेक विडंबनाओं और विसंगतियों के बीच जीती रही है। तमाम मुश्किलों के बावजूद महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। वे घर में मां, बहन, बेटी और पत्नी जैसे रिश्तों को बखूबी निभा रही हैं तो घर से बाहर विभिन्न व्यवसायिक और प्रशासनिक कार्यों से लेकर विज्ञान, कला, खेल और संस्कृति से जुड़े सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और पूरे दमखम के साथ समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दे रही हैं। इन सभी उपलब्धियों के बावजूद महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा का मुद्दा आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है। कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता, जब महिलाओं पर अत्याचार, उनके अपहरण, दुष्कर्म और उत्पीड़न की खबर ना आती हो। महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढते ही जा रहे हैं। महिलाओं का सम्मान करना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना हम सबका सामाजिक उत्तरदायित्व है। कठोर कानून बनाने के अलावा समाज की मानसिकता बदलना भी जरूरी है। जिस तरह महिला शिक्षा को लेकर देश अब जागरूक होता जा रहा है, उसी तरह महिला सुरक्षा के बारे में भी गहन सामाजिक जागरूकता जरूरी है। यह किसी जाति, धर्म, क्षेत्र या राज्य विशेष का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे देश और दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम लगाकर बेटी को बचाया जा रहा है, जैसे स्कूल, कॉलेज भेजकर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब एक मुहिम बेटियों की सुरक्षा के लिए भी शुरू होनी चाहिए।

सबकी बेटियां, हमारी बेटियां

जिस तरह हम अपनी बहन–बेटियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें दूसरों की बहन–बेटियों की सुरक्षा का ध्यान भी रखना चाहिए। याद रखिये, यदि

महिलाएं सुरक्षित हैं तो समाज भी सुरक्षित है। आधी आबादी को असुरक्षित रखकर समाज को विकसित नहीं किया जा सकता। महिलाओं की गरिमा का उचित सम्मान और उनकी समुचित सुरक्षा भी जरूरी है। अंत में:

जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है।

जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं।

अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीं हमने

अभी तो, सारा आसमान बाकी है।

आज महिला दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सदन की माननीय उपाध्यक्षा सुश्री राखी बिरला जी को सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

वो आएं और आज ये सौभाग्य है हम सबका कि हमारी डिप्टी स्पीकर महिला हैं और ये सदन मैं उनको सौंप रहा हूं वो आज इसका संचालन करेंगी। सचिव।

...व्यवधान...

विजेंद्र जी कोई बात नहीं। आप ऐसे करिए। नहीं नहीं एक सेकंड, एक सेकंड भाई। आप यूपी की तरह से मुझे मंत्री नियुक्त करने का इस सदन को अधिकार दिलवा दीजिए हम कर देंगे। एक सेकंड जैसे यूपी में मंत्री 20 प्रतिशत कोटा है तय करने का अधिकार हमें दे दीजिए हम करवा देंगे। चलिए अब हो गया। देखिए अब बात–बात पर विजेंद्र जी, जो चीज जायज हो उनको रखना चाहिए। सचिव, विधान सभा उप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रति इस सदन पटल पर रखेंगे। माननीय सुश्री बिऱला जी। आइए राखी जी।

सचिव (दिल्ली विधान सभा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय उप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।[1]

---

1 दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–21810 पर उपलब्ध।

माननीय उप–राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण,

1. मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सातवीं विधानसभा के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ।

2. बीता साल अभूतपूर्व रहा है। कोविड–19 ने दिल्ली के नागरिकों के जीवन के हर पहलू पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इक्कीसवीं सदी में इस महामारी ने मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न किया। मेरी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए निवारण और इलाज सुनिश्चित करने के लिए सभी संसाधन जुटाए।

3. सरकार ने दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् सहित दिल्ली सरकार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में परीक्षण की क्षमता बढ़ाई। किफायती दर पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए इसकी अधिकतम कीमत तय कर दी गई।

4. क्षेत्र स्तर पर संक्रमितों और उनके संपर्कों का पता लगाने का काम कड़ाई से किया गया। मोबाइल टीमों को उच्च जोखिम वाले समूहों, निगरानी समूहों, प्रवासियों तथा बेघरों की स्क्रीनिंग और परीक्षण के लिए सेवा में लगाया गया। सभी संक्रमितों कंटेनमेंट क्षेत्रों और अन्य क्लस्टरों का Mapping GSDL द्वारा किया गया।

5. सरकार ने कोवडि–19 के प्रत्याशित प्रकोप को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि की। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की सेवाएं लेना तथा इनके लिए अधिकतम मूल्य तय करना और होटलों तथा बैंक्वेट हॉल के साथ संयोजन किया गया।

6. सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि घर पर आइसोलेट होने वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति की दैनिक निगरानी के लिए पल्स ऑक्सिमीटर उपलब्ध कराया जाये और सरकारी डॉक्टरों तथा टेली कॉलिंग के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जाये।

7. लगातार यह सुनिश्चित किया गया था कि कंटेनमेंट जोन में नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं तथा दवाएं निरंतर और समय पर उपलब्ध कराई जाये।

8. जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त में प्लाज्मा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत में पहला प्लाज्मा बैंक, Institute of Liver and Biliary Sciences में और दूसरा लोक नायक अस्पताल में स्थापित किया गया।

9. कोविड–19 से निपटने में अपने जीवन का बलिदान देने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजनों/आश्रितों के लिए 1 करोड रु. की अनुग्रह राशि देने की शुरूआत की गई।

10. हालांकि सरकार के प्रयास कोविड प्रबंधन पर केंद्रित थे, फिर भी अन्य सभी चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में मेडिकल बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा अस्पतालों की Remodeling के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। बुराड़ी और अम्बेडकर नगर में अस्पताल कार्यरत हो चुके हैं।

11. दिल्ली के नागरिकों के कल्याण के उद्देश्य से, मेरी सरकार ने नागरिकों की सहायता के लिए अनेक सार्थक कदम उठाये। लॉकडाउन के कारण आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए मेरी सरकारी ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को वित्तीय सहायता दी। जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन मुफ्त वितरीत किया गया और आश्रय प्रदान किया गया।

12. कोविड के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लगभग 71 लाख लाभार्थियों को अप्रैल, 2020 के दौरान प्रति लाभार्थी 50 प्रतिशत अधिक राशन अर्थात 7.5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया गया।

13. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मई और जून, 2020 का राशन भी दिल्ली सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, PR & PR-S लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 05 किलोग्राम खाद्यान और AAY लाभार्थियों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया गया।

14. ऐसे सभी जरूरतमंद व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें सूखा राशन प्रदान करने के लिए एक विशेष खाद्य राहत पहल–मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शूरू की गई। तदानुसार, अप्रैल और मई, 2020 के दौरान गैर PDS श्रेणी के 54 लाख लोगों को 5 किलो खाद्यान E-Coupon के जरिये मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।

15. आर्थिक तंगी को कम करने के लिए, मई 2020 के महीने के दौरान PDS और गैर PDS परिवारों को आवश्यक–वस्तु किट वितरित करने का प्रावधान भी किया गया। इस किट में आठ वस्तुएं शामिल थीं जिनसे समुचित स्वास्थ्यवर्धक भोजन तैयार किया जा सके।

16. इसके अलावा, ऐसे सबसे कमजोर, निराश्रित और वंचित लोग, जिनके पास राशन कार्ड/ आधार कार्ड नहीं थे, उनके लिए 20,000 से अधिक आपातकालीन राहत कूपन राज्य के सांसदों/विधायकों के माध्यम से गैर PDS योजना के तहत, सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए दिए गए।

17. इस वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली की अर्थव्यवस्था कोवडि–19 से प्रभावित रही है। सरकार इस प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

18. 2020–21 में दिल्ली के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में स्थिर कीमतों पर, 5.68 प्रतिशत कमी होने का अनुमान है। इसके बावजूद दिल्ली के नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मेरी सरकार ने बिजली सब्सिडी, प्रत्येक घर बीस हजार लीटर मुफ्त पानी और डीटीसी बसों में विद्यार्थियों के लिये रियायती और महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की अपनी प्रतिबद्धता कायम रखी।

19. इसी प्रकार लॉकडाउन के दौरान आई आर्थिक गिरावट के कारण रोजगार की हानि हुई है। इस कठिनाई को कम करने के लिए, सरकार ने नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच संपर्क और सामंजस्य के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल – ''रोजगार बाजार'' शुरू किया है। इस पहल के प्रति उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

20. इसके अलावा, मेरी सरकार ने Real Estate Sector को सक्रिय करने के लिए सर्कल रेट को 30/09/2021 तक 20 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है, इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और आम आदमी पर वित्तीय बोझ और कम होगा।

21. समावेशी विकास के लिए मेरी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र पर अपना ध्यान बनाए रखा है। शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे में सुधार और नीतिगत निर्णयों के पहल के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

22. शैक्षणिक सत्र 2019–20 के दौरान सरकारी स्कूलों में बारहवीं कक्षा में पास होने वाले बच्चों की संख्या 97.92 प्रतिशत रही। सत्र 2019–20 के दौरान सरकारी स्कूलों का 10वीं कक्षा में पास प्रतिशत 82.61 प्रतिशत रहा है।

23. सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 578 विद्यार्थियों का चयन भारत सरकार की Merit cum Means छात्रवृत्ति के लिए किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा Cyber Space पर आयोजित अखिल भारतीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता में सरकारी स्कूलों के दो विद्यार्थियों ने शीर्ष दस विद्यार्थियों में स्थान हासिल किया।

24. कोविड–19 के बावजूद, स्कूलों ने कोविड–19 Protocol का पालन करते हंए पहली से आठवीं कक्षा के लिए पाठय पुस्तकों का वितरण किया।

25. खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, अशोक नगर और पश्चिम विहार में क्रमशः Synthetic Hockey Turf और Swimming Pool जैसी नई खेल सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इसी तरह नजफगढ़ में Synthetic Track, Mini Football Field, Basketball Court और कबड्डी Play Field जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

26. प्रशिक्षित और रोजगार योग्य मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, दिल्ली कौशल और उद्यमियता विश्वद्यिालय की स्थापना की गई है।

27. नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का विस्तार करने के लिए, सरकार ने Ambedkar Institute of Advanced Communication Technology and Research, गीता कॉलोनी और चौ. ब्रह्म प्रकाश सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जाफरपुर का इसमें विलय करने का निर्णय लिया है।

28. समाज के गरीब और वंचित वर्गों के प्रति मेरी सरकार का ध्यान केन्द्रित है। विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार संकटग्रस्त महिलाओं, गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह के लिए, साधनविहीन वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

29. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हित में संबंधित विभाग, 08 छात्रवृत्ति योजनाएं चला रहे हैं।

30. जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत SC/ST/OBC और EWS के विद्यार्थियों को Registered निजी कोचिंग संस्थानों से कोचिंग उपलब्ध करा कर UPSC, SSC इत्यादि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मदद करने का लक्ष्य है। इसक योजना के तहत 38 और कोचिंग संस्थानों को सूची में शामिल किया गया है।

31. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना नाम से एक नई योजना अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत कक्षा नौ और दस के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 5,000 हजार रुपये तथा कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी।

32. झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वालों के पुर्नवास के लिए और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने बहुमंजिले रिहायशी मकानों का निर्माण शुरू किया है।

33. DUSIB झुग्गी झोपडी बस्तियों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए पक्के फुटपाथ तथा नालियों की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। सामाजिक सेवाओं के एकीकृत प्रावधान के लिए झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में DUSIB, बस्ती विकास केंद्रों का निर्माण कर रहा है।

34. DUSIB बेघर लोगों को आश्रय भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में यह 193 रैनबसेरों का संचालन और प्रबंधन कर रहा है। इन रैनबसेरों में कोविड 19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

35. मेरी सरकार दिल्ली में श्रमिकों के कल्याण के लिए 44 से अधिक श्रम कानून लागू कर रही है। दिल्ली में पारिश्रमिक की मौजूदा न्यूनतम दर देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक और A श्रेणी के शहरों में लागू केंद्र सरकार की दरों के बराबर हैं।

36. सस्ते मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना, गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। इस उद्देश्य से मेरी सरकार ने 20.2.2021 को मुख्यमंत्री घर–घर राशन योजना अधिसूचित की है। इसके तहत लाभार्थियों को पारदर्शी ढंग से और आसानी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम का मासिक राशन मिलेगा।

37. मेरी सरकार ने शहर में पानी की आपूर्ति सफलतापूर्वक की है। जल उत्पादन 935 MGD पर बनाए रखा गया है। अनाधिकृत कालोनियों में पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए पाईप नेटवर्क उपलब्ध कराया जा रहा है। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए पुरानी और जंग खा चुकी लाईनों को हटाकर नई पाईपलाइनें बिछाई जा रही हैं।

38. यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, प्रस्तावित नये STP, नवीनतम तकनीक के साथ लगाए जा रहे हैं ताकि चरणबद्ध रूप से उपचार गुणवत्ता प्राप्त की जा सके। STPs को स्वयं पोषित बनाने के लिए उपचारित कचरे से बिजली पैदा किये जाने के कार्य भी किये जाने की योजना है। इससे बिजली के बिल में भी बचत होगी।

39. यमुना कार्य योजना–III के तहत, दिल्ली जल बोर्ड रिठाला, कोंडली और ओखला में STPs के पुर्नवास/पुनःनिर्माण का कार्य कर रहा है। 35 किलोमीटर लंबाई की संबंधित ट्रंक सीवर और मुख्य नालियों पर कार्य भी प्रगति पर है।

40. माननीय सदस्यगण,

दिल्ली ने 6314 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग को 29 जून 2020 को Zero Loadshedding के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया। दिल्ली में बिजली शुल्क पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे कम है।

41. दिल्ली सरकार ने दिल्ली में औद्योगिक प्रगति के लिए कई पहल किये हैं। नांगली–सकरावती औद्योगिक Cluster, उद्योग विभाग द्वारा पुर्नविकास के लिए अधिसूचित किया गया है।

42. दिल्ली में Infrastructure विकास के लिए दिल्ली सरकार ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं। शास्त्री पार्क और सीलमपुर में फ्लाईओवर यातायात के लिए खोल दिया गया है।

43. प्रगति मैदान के अंदर और आसपास Integragted Transit Corridor विकास योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

44. बारापूला नाले पर सराय काले खॉ से मयूर विहान फेज–3 तक Elevated सड़क का निर्माण कार्य जारी है।

45. वजीराबाद और जगतपुर के बीच दो वाहन Underpass तथा आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट पैदल पारपथ का निर्माण कार्य जारी है। यह कार्य जल्दी ही पूरा हो जाने की आशा है।

46. आडटर रिंग रोड पर IIT से NH-8 और इसके आसपास के क्षेत्रों में कॉरिडोर सुधार के लिए मुनिरका फ्लाई ओवर चालू हो गया है और इसके अलावा Underpass का निर्माण कार्य चल रहा है।

47. मेरी सरकार, दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिये 1000 लो फ्लोर बसों और 1000 बिजली चालित बसों को खरीदने का काम कर रही है।

48. दिल्ली मेट्रो का मौजूदा नेटवर्क एनसीआर सहित 348 किलोमीटर का है। मेट्रो के Phase-3 के तहत मयूर विहार पॉकेट–1 से त्रिलोकपुरी तक का खंड मार्च 2021 तक पूरा हो जाना निर्धारित था और ढांसा बस स्टैंड तक इसके विस्तार का काम सितंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाना है। Phase-3 के शेष दो छोटे खंडों का निर्माण कार्य और Phase-4 के स्वीकृत तीन प्राथमिकता कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

49. मेरी सरकार ने दिल्ली Electric वाहन नीति अधिसूचित कर दी है। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में तेजी से Electric वाहनों को बढ़ावा देना है और इन वाहनों के लिए आवश्यक Charging Infrastructure स्थापित करना है। Electric वाहनों को, खरीद प्रोत्साहन, पुराने वाहन हटाने पर प्रोत्साहन, ऋण पर ब्याज में छूट, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट और Charging तथा Swappable Battery स्टेशनों का Network स्थापित कर, प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस नई पहल से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

50. सरकार ने शहर के पर्यावरण में सुधार और प्रदूषण की रोकथाम पर पूरा ध्यान दिया है। इसके लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें व्यापक कार्य योजना–CAP और Graded Response Action Plan-GRAP शामिल हैं। पर्यावरण, प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण – EPCA की सिफारिशों के अनुसार 15 अक्टूबर 2020 से GRAP के तहत संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं।

51. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति नगर में 26 स्थलों पर Real Time Basis पर आठ वायु गुणवत्ता मानदंडों पर लगातार नजर रख रही है।

52. किसानों द्वारा धान के खेतों में पराली जलाए जाने से होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने IRAI, पूसा के वैज्ञानिकों के साथ व्यापक प्रबंध किया है। दिल्ली में गैर–बासमती धान के खेतों में दो हजार एकड़ पर,

खेतों तक पराली लाकर उन पर Bio Decomposer घोल के छिड़काव की व्यवस्था की गई है।

53. लोगों में जागरूकता लाकर यातायात Inter Sections पर वाहन प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने ''रेड लाईट ऑन, गाड़ी ऑफ'' अभियान की शुरूआत की है। शुरू में यह अभियान यातायात पुलिस के साथ 2500 Civil Defence Volunteers की मदद से 21.10.2020 से 25 दिनों के लिए 100 प्रमुख Inter Sections पर चलाया गया। आम लोगों की सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसे 30.11.2020 तक बढ़ा दिया गया।

54. प्रदूषण से संबंधित किसी भी मामले को दर्ज करने के लिए आम लोगों के लिए 24 घंटे, सातों दिन प्रदूषण निगरानी तंत्र के साथ Green War Room और Green Delhi App की शुरूआत की गई। Green War Room में तैनात टीम शिकायतों पर बारीकी से नजर रखती है। संबंधित विभागों और पूरी दिल्ली में फैली 14 मोबाइल टीमों के द्वारा इन शिकायतों की जांच और उनपर कार्रवाई की जाती है।

55. दिल्ली में कोरोना महामारी डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों, वैज्ञानिकों, सफाई कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों के कारण नियंत्रण में है। नागरिकों ने भी निर्धारित दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर इस माहामारी का फैलाव रोकने में मदद की है। मेरी सरकार हर एक पक्ष के योगदान की सराहना करती है। उन लोगों के योगदान और समर्पण की भी सराहना आवश्यक है जिन्होंने पानी, बिजली और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी।

56. मेरी सरकार प्रत्येक नागरिक से दिशा–निर्देशों के अनुरूप कोरोना वैक्सीन लेने और निर्धारित ऐहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने की ज्ञी अपील करती है ताकि संक्रमण के फैलाव पर पूरी तरह अंकुश रखा जा सके।

57. माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन के सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष संक्षेप में अपनी सरकार की कुछ गतिविधियों की चर्चा की है। उप मुख्यमंत्री/वित्तमंत्री आगे अपने बजट भाषण में इनका विस्तार से उल्लेख करेंगे।

58. मैं सदन में सार्थक विचार–विमर्श की कामना करता हूँ और सदन के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए प्रार्थना करता हूँ आप सब को बधाई।

जय हिन्द

Hon'ble Lt. Governor's Address

Hon'ble Speaker and Members,

1. I welcome you all to the Second Session of the Seventh Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi.

2. The year gone by has been unprecedented. COVID-19 has adversely affected every aspect of life of citizens of Delhi. The Pandemic created greatest threat to the human life and health ever witnessed in the twenty-first century. My Government together with the Central government garnered all resources to ensure preventive and curative actions to safeguard the life of citizens of Delhi.

3. The Government ramped up the testing capacity in all Delhi Givernement helath facilities, Private Hospitals & Nursing Homes including MCDs and NDMC. Cost of tests was capped for affordable access to testing.

4. Rigorous tracking and tracing activities at field level were undertaken. Mobile teams were pressed into service for screening & testing of high risk groups, special surveillance groups, migrants and homeless. Geo-mapping was done by GSDL of all positive cases, Containment Zones and other Clusters.

5. The Government increased bed capacity well in advance of the anticipated outbreak. On-boarding of private hospitals/nursing homes, price capping, linkages of hotel accomodations and banquet halls are some of the initiatives in this regard.

6. The Government ensured that, patients under home isolation were provided Pulse Oximeters and Teleconsulations by Government Doctors and Tele Calling for daily monitoring of their health status.

7. It was consisently ensured that continuous and timely delivery of essential items and essential medicines were made to the citizens in Containment Zones.

8. First Plasma Bank in India was set up at Institute of Liver and Biliary Sciences and second at Lok Nayak Hospital for ensuring availability of plasma, free of cost to the needy patients.

9. Ex-gratia compensation of Rs. 1 Crore has been instituted for the families/dependents of the Corona Warriors who sacrificed their lives in the battle against COVID.

10. Though efforts of the Government were focused on COVID management yet all other medical services were ensured. To enhance the bed capacity in Delhi, Delhi Govt. has initiated various steps for construction of new hospitals and re-modelling of existing hospitals. The hospitals at Burari and Ambedkar Nagar are operational.

11. With the motto of welfare of citizens of Delhi, my Government extended its hand to provide succour to the citizens. To overcome economic Challenges due to lockdown my Governement gave financial assistance to taxi and auto rickshaw drivers. Free distribution of cooked meals was undertaken and shelter to the needy was provided.

12. In order to address the food needs of PDS beneficiaries due to the impact of the restrictions imposed to prevent the spread of COVID, 50% enhanced ration i.e. 7.50 Kg of food grains per beneficiary was provided free of cost to about 71 Lakhs PDS beneficiaries during the month of April, 2020.

13. Ration under NFS for the month of May & June, 2020 also were made free of cost by the Delhi Government. Also, regular entitlement of 05 Kg. of food grains per person for PR & PR-S beneficiaries and 35 Kg.

of food grains for AAY beneficiaries per household was provided free of cost.

14. A special food relief intiative, Mukhya Mantri Corona Sahayata Yojana was launched to provide dry ration to all persons in need of food and not in possession of ration card. Accordingly, provision of 5 kg of food grains per beneficiary member for the month of April and May, 2020 was made against e-coupons free of cost to more than 54 Lakhs individuals under Non-PDS category who were not covered under regular Public Distribution System.

15. Further, in order to reduce the economic hardship, another provision was made to distribute one "Essential item kit" per household during the month of May 2020, to both PDS and Non PDS households. The kit comprised eight items to enable households to prepare decent hygienic meals.

16. In addition to the above, 20,000 emergency relief coupons were also made available through MPs/MLAs of the State for availing dry ration under non-PDS scheme to the most vulnerable, destitute and disadvantaged people who were in need of food but did not have Ration Card/Aadhar Card.

17. All economies have been dented by COVID-19 and so has the economy of Delhi. Gross State Domestic Product of Delhi in real terms at constant prices is estimated to have contracted by 5.68% in 2020-21. Yet, in order to ease the life of citizens of Delhi my Government continued with its commitment of electricity subsidy; twenty thousand liters of free water to domestic household and concessional ride for students and free ride for women in DTC buses.

18. Delhi's economy has been impacted by COVID-19 in this Financial Year. The Government is taking all necessary measures to cushion the impact and bring the economy back to track.

19. One of the main fall out of the lockdown period has been dislocation of employment. To mitigate the hardship, the Government has launched a dedicated web portal 'Rozgar Bazar' to help both the job seeker to get employment and the employers to hire the required manpower. There has been overwhelming response to this initiative.

20. Further, my Government has decided to reduce the Circle Rate by 20% till 30/09/2021 in order to activate the realty sector which will boost the economy of Delhi. It will further reduce the financial burdern on the common man.

21. For inclusive growth my Government has maintained its focus on education sector. The initiatives taken for transforming the education sector by way of improvement in infrastructure, policy decisions etc. have resulted in delivery of higher level quality education.

22. Govt. Schools recorded pass percentage of 97.92% in class 12th during academic session 2019-20. At the 10th level pass percentage of Govt. schools in 82.61% during academic session 2019-20.

23. 578 students of Govt. and Govt Aided Schools were selected to receive Merit-cum-Means Scholorships provided by Government of India. Two students of government schools achieved place in top ten students in the Essay Competition organized by Indian Space Research Organization (ISRO) on all India Level competition on cyberspace.

24. Despite COVID-19 situation, schools distributed text books (Class I to VIII) by observing COVID-19 protocols.

25. With the aim to promote sports, new sports facilities Synthtic Hockey Turf and Swimming Pool have been constructed at Ashok Nagar and Paschim Vihar respectively. Similarly, at Najafgarh, Stadium facilities like Synthetic Track, Mini Football Field and Basketball Court, Kabaddi Playfield are available.

26. In the field of higher education, Delhi Skill and Entrepreneur University has been setup to address the challenge of developing trained and employable human resource.

27. To expand Netaji Subhash University of Technology, Government has decided to merge Ambedkar Institute of Advanced Communication Technologies & Research, Geeta Colony and Ch. Braham Prakash Goverment Engineering College, Jaffarpur with NSUT.

28. My Government's attention to the poor and marginalised sections of society remained unfettered. Government provides financial assistance to women in distress, to poor widows for performing marriage of their daughters, to old person without any means of substance and persons with disabilities. Further, financial assistance is also provided under National Family Benefit Scheme.

29. For the welfare of persons belonging to SC/ST/OBC/Minorities category, Department concerned is implementing 08 scholarship schemes.

30. Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojana, was envisaged for assisting students belonging to SC/ST/OBC/EWS category to appear in various competitive examinations conducted by UPSC, SSC etc. and entrance exams for professional courses, by way of providing coaching through empanelled private coaching institutes. 38 more coaching institutes have been taken on panel under this scheme.

31. A new scheme namely Mukhyamantri Vidhyarti Pratibha Yojna for SC/ST/OBC/Minority students has been introduced. Under this scheme students of Class 9th and 10th will be provided Scholorship amount of Rs.5,000/- per annum and for Class 11th & 12th students Rs. 10,000/- per annum will be provided as scholorship.

32. To rehabilitate residents of JJ Bastis and to provide them dignified life, Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) has taken

up construction of multi-storey dwelling units for slum dwellers for rehabilitation of eligible JJ dwellers.

33. DUSIB is providing the facility fo paved pathways/drains in JJ Basti to improve the standard of living. DUSIB is also providing the built-up space in JJ Basties in the form Basti Vikas Kendras for provision of integrated package of services under the social consumption section.

34. DUSIB also provide shelter to shelter-less population. At present, DUSIB is operating and managing 193 shelters homes. COVID-19 protocols are being followed in these shelter homes.

35. My Government enforces more than 44 Labour Laws in Delhi for welfare of labourers. The present rates of minimum wages in Delhi are highest among, all the States and Union Territoris in the country and at par with the Central Government rates in A-class cities.

36. It is necessary to ensure access to adequate quantity of quality food at affordable prices to live a life with dignity, My Government has notified Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojna on 20.02.2021. Under this scheme, the beneficiaries will receive monthly ration under National food security scheme in a transparent manner with miximum ease.

37. My Government has successfully met the demand of water of the city. Water production has been maintained at 935 MGD. For improved water supply in un-authorized colonies, piped water supply networks are being provided in unauthorized colonies. For ensuring safe drinking water supply, new water pipelines are biend laid, old and rusted water lines are being replaced.

38. For improvement of quality of Yamuna river water, all the proposed new STPs are being set up with latest technology to achieve higher treatment quality standards in phased manner and generation of power from the treatment waste to make the STP self-sustainable resulting to saving in power bill.

39. Under Yamuna action Plan-III, DJB is taking up the work of rehabilitation/reconstruction of sewage treatment plants at Rithala, Kondli & Okhla and also rehabilitation of connected trunk sewers and rising mains in a length of 35Kms.

40. Hon'ble Members,

Delhi Successfully met the peak power demand of 6314 MW recorded on 29th June, 2020 with zero load-shedding at the time of peak demand. Delhi Electricity Tarif remains lowest among neighbouring states.

41. Govt. of Delhi has taken a number of initiatives for progress of Industrial setup in Delhi. Nangali-Sakrawati Industrial Cluster was notified for redevelopment by Industries Department.

42. For development of infrastructure of Delhi, my Government has initiated number of projects. Flyovers at Shastri Park and Seelampur has been opened to public.

43. Construction of integrated transit corridor development plan in and around Pragati Maidan is in progress.

44. Work for construction of elevated road over Barapullah Nallah starting from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar (Phase-III) is in progress.

45. Construction of two vehicular under passes between Wazirabad & Jagatpur and one pedestrian subway near Gandhi Vihar on Outer Ring Road, Delhi is under way. Entire work is expected to be completed in the near future.

46. For the corridor improvement of Outer Ring Road from IIT to NH-8 & its influence areas, Munirka Flyover was made operational. Further, construction of underpass work is under progress, majority of work has been completed.

47. My Government is focused on strengthening the Public Transport Infrastructure in Delhi. To strengthen the transport infrastructure, the process of procurement 1000 low floor buses and 1000 pure electric buses are under progress.

48. The existing network of Delhi Metro is 348 Kms including extension to the NCR. Under Phase-III of Metro, Mayur Vihar Pocket-I to Trilokpuri stretch is scheduled to be completed in March, 2021 and extension to Dhansa Bus Stand is Scheduled in September, 2021. The works at construction sites of remaining two small stretches of DMRTS phase-III and sanctioned three priority corridors of phase-IV have resumed.

49. My Government has notified Delhi Electric Vehicle Policy. The policy aims to encourage the rapid adoption of electric vehicles in Delhi and establishing a necessary charging infrastructure for electric vehicle at an accelerated pace through implementation of purchase incentive, scrapping incentive, interest subvention on loans, waiver of road tax and registration fees, and establishment of network of charging and swappable battery stations. This will also help environment conservation.

50. Government has focused attention to improve the environment of the city and to check pollution. Number of actions has been taken which include implementation of Comprehensive Active Plan (CAP) and Graded Response Action Plan (GRAP). As per recommendation of Environment, Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA), provisions of very poor/severe category of Graded Response Action Plan (GRAP) has been enforced from 15th October, 2020.

51. Delhi Pollution Control Committee (DPCC) is constantly monitoring eight ambient air quality parameters on real time basis at 26 locations in Delhi.

52. To mitigate severe air pollution generated by stubble burning in paddy fields by the farmers, Delhi Government in coordination with scientists of

IARI, PUSA arranged bulk preparation, transportation up to the fields and sprinkling of Bio-Decomposer solution in 2000 acres of total Non-Basmati paddy fields of Delhi.

53. To control vehcular pollution at traffic intersection by way of awareness and persuasion, the government launched a campaign "Red Light On, Gaadi Off" at 100 major intersections of Delhi, initially for 25 days with effect from 21.10.2020 with the help of 2500 Civil Defence Volunteers along with Traffice Police. After observing the encouraging response from general public, this campaign was extended till 30.11.2020.

54. Green War Room with 24 x 7 live pollution monitoring mechanism and Green Delhi App were launched for the general public to register any pollution related issue and the team stationed in the Green War Room keeps a close watch on the redressal of these complaints through concerned Departments and further cross checking the same by way of 14 mobile teams spread throughout Delhi.

55. COVID-19 pandemic is under control in Delhi due to collective efforts of medical profesional, Scientists, Sanitation workers, members of Security forces and to the Civil Administration and also due to cooperation extended by citizens by following the norms laid down. My Government appreciates the contribution made by all. My Governmnet also appreciates the devotion to duty of all who ensured uninterrupted water, electricity and essential services.

56. My Government appeals to every citizen to avail vaccination as per guidelines issed by the Government and continue to strictly follow the COVID-19 norms as the pandemic continues to prevail.

57. Hon'ble Speaker and Members of the august house, I have presented before you, in brief, the some of the activities undertaken by my Government. Dy. Chief Minister/Finance Minister will spell out further details in his Budget Speech.

58. I wish all success in your deliberations. I pray for well-being of the members of this august House and extend my warm greetings to all.

Jai Hind

माननीय उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री राखी बिरला) पीठासीन हुई।

माननीय अध्यक्षा : अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 प्रस्तुत करेंगे।

माननीय उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 की हिन्दी और अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्षा : एक सेकेंड, पहले बोलने। मैं अनिल बापजेयी जी आपको समय दूंगी। बाजपेयी जी पहले आप मेरी सुन लेंगे। बाजपेयी जी पहले आप मेरी सुन लें। आप मेरी सुनेंगे एक मिनट। मैंने आपको, मैंने आपको बिल्कुल भी आज्ञा नहीं दी है। माननीय उप–मुख्यमंत्री जी। मनीष सिसोदिया जी।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षा : आपको मंत्री जी से मैं।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षा : मैं आपकी जो बात है एक सेकेंड अखिलेश त्रिपाठी जी। अनिल जी आपकी जो बात है जो भी आप मंत्री जी से जवाब चाहते हैं वो आपकी सुनी भी जाएगी और जो मंत्री जी से आप जवाब चाहते हैं वो भी दिया जाएगा। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे हैं, दो मिनट आप बैठ जाइए। बैठ जाइए विजेन्द्र गुप्ता जी। आप शुरू रखिए।

माननीय उप–मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्षा महोदय मैं आपकी अनुमति से सदन का आर्थिक सर्वेक्षण।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षा : जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं और समय लेकर नहीं खड़े होंगे, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप बैठिए। आप नहीं बैठेंगे तो आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप अनुशासन में रहें। आपको समय दिया जाएगा। माननीय सदस्य आप लोगों को पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन जो शेड्यूल्ड है उसको पूरा कर लेने दीजिए। अगर आप इस तरीके से बीच में बात उठाएंगे तो पूरा नहीं होगा। आप बैठिए। आप क्या चाहते हैं आपकी बात को सुना जाए या शोर? नहीं दो मिनट। विजेन्द्र गुप्ता जी आप सब लोग विपक्ष के साथी मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य आपकी बात को कंसीडर कराना है या शोर मचाना है। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य अपनी बात को मनवाना है। आपका उद्देश्य अपनी बात मनवाना है तो उसको सही ढंग से उठाइए न। शोर मचाना उद्देश्य है तो शोर तो नहीं सुना जायेगा। आपकी दरख्वास्त को माना जायेगा बशर्ते कि आप उसे सही तरीके से पेश करें। जब तक आप इस तरीके।

.....व्यवधान.....

आप, नहीं तो ये direction आप नहीं देंगे न। अभी एक उप–मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं न। आप बैठिए। आप सब लोग बैठिए। मुझे नहीं लगता आपका उद्देश्य अपनी बात रखवाना है। मुझे नहीं लगता। मैं बहुत माफी के साथ कह रही हूं। भाजपा के साथियों का, विपक्ष का मुझे नहीं लगता उद्देश्य अपनी बात मनवाना है। आप बैठिए न फिर। चार लोग एक साथ बोलेंगे। तो रूलिंग दे तो रहे हैं। जब तक विजेन्द्र गुप्ता जी नहीं बैठेंगे कन्सीडर नहीं किया जायेगा। इनकी एक भी बात को रिकार्ड में नहीं लिया जाये। जब तक आप समय लेकर अपनी बात को नहीं। आपका उद्देश्य सिर्फ शोर मचाना है। आपकी बात, आपको अपनी बात रखने का उद्देश्य। बिल्कुल तय करेंगे। पहले उप–मुख्यमंत्री जी को बोल लेने दीजिए। उप–मुख्यमंत्री जी को बोलने दीजिए। आपको समय देंगे। शान्ति बनाये रखिए न। शोर मचाना लक्ष्य है? अगर शोर मचना लक्ष्य नहीं है तो शान्ति बनाये रखें। माननीय उप–मुख्यमंत्री जी

को अपना सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है वो पेश करने दीजिए। अगर शोर मचाना लक्ष्य है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जी।

माननीय उप–मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 हिन्दी व अंग्रेजी की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।[2]

माननीय अध्यक्षा : अब श्री दिलीप कुमार पाण्डेय जी कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री दिलीप पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।[3]

माननीय अध्यक्षा : अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के आउटकम बजट 2020–2021 की 31 दिसम्बर, 2020 तक की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

माननीय उप–मुख्यमंत्री : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के आउटकम बजट 2020–21 की 31 दिसम्बर, 2020 तक की स्टेटस रिपोर्ट की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं[4] और इसे प्रस्तुत करते हुए उसके सम्बन्ध में कुछ बातें भी सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये सर्वविदित है कि पिछले चार वर्षों से दिल्ली सरकार ने एक नई परम्परा इस सदन में शुरू की थी और वो ये थी कि इस सदन में आउटकम बजट भी प्रस्तुत किया जायेगा। अभी तक भारत में देश भर की विधान सभाओं में ये परम्परा रही हैं कि हम बजट पेश करते हैं और उसमें उसके कुछ आउटपुट निर्धारित करते हैं और मूलतः वो आउटपुट जो होता है वो खर्चे से सम्बन्धित होता है लेकिन दिल्ली सरकार ने पहल करते हुए, दिल्ली के वित्त मंत्रालय ने पहल करते हुए पहली बार आउटकम

---

2 दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–21830 पर उपलब्ध।

3 दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–21811 पर उपलब्ध।

4 दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–21831 पर उपलब्ध।

बजट भी एक नई कान्सेप्ट इन्ट्रोड्यूस की और पिछले चार साल से हम लगातार इस सदन में बजट से पहले आउटकम बजट पिछले साल का पेश करते हैं। ये अपने आप में सरकार को जवाबदेह बनाने की इस विधान सभा के प्रति एकाउन्टेबल बनाने की एक अनूठी प्रक्रिया है जिसका मैं समझता हूं कि पूरे देश में इसका कोई और ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। इसमें जो सदस्य पिछले बार इस प्रक्रिया में शामिल नहीं थे या जिनके ध्यान में न हो उनकी सूचना के लिए भी मैं रखना चाहता हूं। इसको पुनः रेखांकित करना चाहता हूं कि आउटकम और आउटपुट दोनों अलग–अलग चीजें हैं। हम बजट में आउटपुट भी बताते हैं और आउटकम भी बताते है। चार साल से जो दिल्ली सरकार का बजट बढ़ाया जाता है, उसमें दोनों इंडिकेटर होते हैं। मान लिजिए किसी हॉस्पिटल में कोई मशीन खरीदनी हैं तो उस मशीन को खरीदने के लिए बजट में मान लिजिए 10 करोड़ का प्रस्ताव है तो 10 करोड़ की वो मशीन खरीद ली गयी कि नहीं खरीद ली गयी वो उसका आउट–पुट है। लेकिन उस मशीन को वहाँ लगाकर उस पर जो भी आवश्यक मैन पावर है वहाँ लगाकर उस मशीन से जिन लोगों की स्कैनिंग होनी थी, जिन लोगों का इलाज होना था, वो इलाज शुरू हुआ कि नहीं हुआ। कितने लोगों का इलाज शुरू हुआ, वो आउटकम है। तो सामान्यतः सरकारी प्रक्रियाओं में बजट की प्रक्रियाओं में मशीन अगर खरीद ली गयी और यहाँ आकर विधान सभा को वापस बता दिया गया साहब कि आपने हमारे लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किये थे, हमने आपकी मशीन खरीद के वहाँ पर लगा दी है, इसको इतिश्री मान लिया जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने इफैक्टिव आउटकम यानी इन्श्योर करने के लिए ये परम्परा शुरू की कि मशीन खरीदने भर से काम नहीं चलेगा, ये भी देखना होगा कि उस मशीन पे कितने लोगों का टेस्ट हुआ तो अब हम ये रिपोर्ट भी आपके पास लेकर आते हैं, तो ये आउटकम बजट में इस तरह से हरेक विभाग का ये जो बजट इस विधान सभा से पास किया जाता है, उस बजट से क्या क्या काम होंगे, क्या क्या कैपिटल इंवेस्टमेंट होंगे, क्या क्या योजनाएं लागू होंगी, ये बताया जाता है और उन योजनाओं से कितने लोगों को फायदा होगा, उसका अल्टीमेट आउटकम क्या है, उसमें उसकी नीयत क्या थी, उसका इरादा क्या था क्योंकि मशीन खरीदने का इरादा नहीं था। इरादा तो लोगों का इलाज करना था। मशीन खरीदने भर से संतुष्ट होने वाली सरकार ये सरकार नहीं है, केजरीवाल जी

की। मशीन खरीदने के बाद अगर इन्स्टॉल हुई तो उसके बाद आउटकम क्या रहा। लोगों का इलाज हुआ कि नहीं हुआ, इसको मैंने एक उदाहरण से समझाने की कोशिश की है। हमने हर साल के बजट में आउटपुट और आउटकम दोनों इंडिकेटर डाले हैं। मैंने पिछली बार भी जब बजट पेश किया था, उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी महामारी के मुहाने पर हम बैठे हैं तो बड़े लक्ष्य रखकर सरकार की ओर से आउटकम इंडिकेटर्स बनाये गये थे और आउटपुट इंडिकेटर्स बनाये गये थे तो मैं चौथे साल के अपने इस आउटकम बजट में कुछ चीजें यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी के दौरान दो बड़ी चुनौतियाँ आयीं। एक तो लॉक डाउन, जिसकी वजह से सामान्य सरकारी गतिविधियाँ, हैल्थ को छोड़कर और कोविड मैनेजमेंट को छोड़कर, सरकारी गतिविधियाँ लगभग लगभग कुछ महीनों के लिए तो पूरी तरह से बंद की गयी और फिर धीरे–धीरे उनको अंशतः खोला गया। उसमें समय लगा। दूसरा कोविड की वजह से जो वक्त बीता, उसमें सरकार के पास क्योंकि मार्केट में बिजनेस कम हुआ, मार्केट में बिजनेस कम होने की वजह से सरकार के पास रेवेन्यू भी कम हुआ, उसकी वजह से भी आर्थिक तंगी, आर्थिक हालात थोड़े कमजोर रहे। उसकी वजह से भी कुछ योजनाओं पर हम उतना खर्च नहीं कर पाए जितना हमसे अपेक्षित था। लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ कि इस महामारी के बीच हमारी सरकार के तमाम् विभागों ने हैल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बहुत शानदार काम किया। विशेषकर राजस्व विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर शिक्षा विभाग ने, उच्च शिक्षा विभाग ने, यातायात, श्रम विभाग ने तमाम् विभागों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर इस महामारी में अपनी मूल जिम्मेदारियाँ, जो परम्परागत जिम्मेदारियाँ हैं, उनसे हटकर, सड़क पर खड़े होकर, हॉस्पिटल्स में खड़े होकर, कंटेंटमेंट जोन में खड़े होकर हॉस्पिटल्स के बाहर लोगों की मदद करके, हर तरीके से मजदूरों की मदद करके, यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों को खाना खिलाकर टीचर्स तक ने रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने सबने इसमें बहुत अभूतपूर्व भूमिका निभायी तो मैं सदन के समक्ष सबसे पहले तो उनकी प्रशंसा में मैं चाहता हूँ कि ये सदन उसको एप्रिसियेट करे और उनको यहाँ से सब लोगों ने जो अभूतपूर्व भूमिका निभायी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि उस अभूतपूर्व संकट के बीच

भी जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे, जो सरकारी विभाग थे उनकी जो मूल जिम्मेदारी थी, उसको भी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। उसपर भी लगातार काम करते रहे तो हमने जो इंडिकेटर्स आपने बनाये थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए मैं उनपर भी प्रोग्रेस क्योंकि एलजी साहब की स्पीच में भी कोविड मैनेजमेंट के बारे में काफी वक्तव्य रहा है कि किस तरह से शानदार कोविड मैनेजमेंट रहा। तो मैं अपनी स्पीच के उस हिस्से को दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से और विस्तार से उन चीजों का जिक्र किया है माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कि किस तरह से कोविड मैनेजमेंट में इन सब डिपार्टमेंट्स ने भूमिका निभाई और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कोविड मैनेजमेंट में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए भी इन डिपार्टमेंट्स ने अपना मूल कर्तव्य जो आउटकम यहां पर सुनिश्चित करके बजट दिया गया था, उसको कैसे निभाया। आगे मैं उसको थोड़ा सा रेखांकित करना चाहता हूं। शुरूआत में शिक्षा निदेशालय के कार्यक्रमों से करूंगा जो शिक्षा निदेशालय ने Parenting in the time of Corona मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में Parenting in the time of Corona के नाम से पूरा अभियान शुरू किया कि बच्चे घर पर बैठे हैं तो उनकी पढ़ाई न छूट जाए। इसलिए अभिभावकों के साथ मिलकर हर घर में क्योंकि पहले स्कूल में पढ़ाई होती थी। लेकिन हर घर में हरेक अभिभावक एक शिक्षक की भूमिका निभा सके इसलिए Parenting in the time of Corona के साथ में पढ़ाई की शुरूआत कराई pandemic के समय पर भी और उसके बाद ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन मदद से और इसमें हमारे शिक्षकों ने बहुत शानदार भूमिका निभाई। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से जो क्लासिज सामान्यतः 220 दिन की होती थी। इस बार क्योंकि ऑनलाइन था 229 दिन हमारी क्लासिज लगी है लॉकडाउन के बावजूद और इसमें 98 परसेंट बच्चों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन में भागीदारी की। ग्यारहवीं और बारहवीं के क्लास में 89 से 98 परसेंट अलग–अलग स्कूलों में रहा। लेकिन 89 से 98 परसेंट तक की भागीदारी स्कूलों में बच्चों की रही ऑनलाइन क्लासिज में। इस तरह से हम एक तरह से किसी भी बच्चे की शिक्षा न छूटे मिनिमम नुकसान हो वो उसको एंश्योर करने में कामयाब रहे। पहली से आठवीं क्लास के लिए पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया और छात्राओं को सैनिटरी नेपकिन तक बांटे ऐसे संकट के समय में। तो इस तरह से शिक्षा निदेशालय ने जो काम किया उसके बेस पर मैं

अगर कहूं तो 2020–21 आउटकम बजट में हमने 37 स्कीम शामिल की थी और उन 37 स्कीम्स में से हमने 182 पर आउटपुट, आउटकम इंडीकेटर तय किए थे 182 तरह के इंडीकेटर्स हमने निकाले थे। इसमें से 44 संकेतक इंडीकेटर बहुत महत्वपूर्ण थे। तो जो आउटकम है इस बार का कि इन 44 में से 37 पर हमारा पूरा काम ऑन ट्रैक रहा, 7 इंडीकेटर्स पर हम ऑफट्रैक रहे उतना काम नहीं कर पाए जितना हमसे अपेक्षित था जितना की हमने तैयारी की थी। महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स में देखें तो Right to Education Act के तहत आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के 35275 विद्यार्थियों का निजी स्कूल में दाखिला कराया। सरकारी स्कूलों ने बारहवीं के स्तर पर शिक्षा सत्र 2019–20 में 97.92 लगभग 98 परसेंट का पासिंग परसेंटेज दर्ज किया, जबकि पिछले साल ये 94 परसेंट था। दसवीं क्लास के स्तर पर सरकारी स्कूलों का पासिंग परसेंटेज 82.6 रहा, जबकि पिछले साल ये 70.58 परसेंट था। सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासिज में 7.87 लाख, 7 लाख 87 हजार विद्यार्थी 2020–21 के दौरान मिड डे मिल योजना से भी लाभान्वित हुए। लॉकडाउन के बावजूद उनको मिड डे मिल पैक्ड कर उनके घर पर जिस तरीके से पहुंचाया गया। 728 सरकारी स्कूल भवनों में से जो हमारा काम पहले हमने इंडीकेटर में तय किया था दिसंबर तक 459 में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम पूरा हो गया था और ये और भी आगे अब बढ़ चुका है वर्तमान में मैं जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी तरह से हायर एजूकेशन डायरेक्ट्रेट ने 2020–21 के आउटकम बजट में 13 कार्यक्रम और स्कीम शामिल किए थे जिसमें 234 आउटपुट इंडीकेटर्स हमने इसमें बनाए थे। इनमें से 61 महत्वपूर्ण थे इसकी प्रोग्रेस ये हैं कि 84 परसेंट यानि कि 51 इंडीकेटर्स पर ऑनट्रैक है सही से पूरे सेटिसफेक्ट्री काम हुआ। 16 परसेंट यानि कि 10 इंडीकेटर्स ऐसे हैं जिन पर ऑफट्रैक रहे जिन पर हम सेटिसफेक्ट्री काम नहीं कर सके हम सतुंष्ट नहीं हुए उससे। महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स में देखे तो आईपी यूनिवर्सिटी का जो ईस्ट कैंपस है उसका निर्माण कार्य 2017 में शुरू किया गया था। तो पीडब्लूडी ने दिसंबर 2020 तक की जो रिपोर्ट दी है उसमें 80 परसेंट वो उस वक्त तक कंप्लीट हो चुका था। दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कालेजों में वर्ष 2020–21 में कुल 8248 नए स्टूडेंट नामांकित किए गए। 19–20 के दौरान 7539 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था। 2020–21 के दौरान Merit Cum

Means Linked Financial Assistance Scheme के तहत 3760 विद्यार्थियों को financial assistance उपलब्ध कराई गई दिल्ली सरकार की ओर से। Technical Education Department में 26 कार्यक्रम स्कीम शामिल की गईं थी जिसमें 331 outcome indicators शामिल किए गए थे 129 इसमें से बहुत महत्वपूर्ण थे। रिपोर्ट को देखें तो on track 103, 80 परसेंट जो हैं इसके 129 के on track हैं और 26 इंडीकेटर्स यानि 20 परसेंट off track हैं। महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स में से 2021 में यूजी और पीजी तकनीकी कॉलेज विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या बढ़कर 9531 हो गई जबकि पिछले साल वो 8423 थी। दिसंबर महीने तक Polytechnic diploma पाठ्यक्रम में 41000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। पीएचडी कार्यक्रम में 393 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया और 106 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई क्योंकि रिसर्च हमारे कॉलेज और युनिवर्सिटीज में अब बढ़ रही है ये इस बात का इंडीकेटर है। अलग–अलग technical colleges और विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे 2798 विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट मिला, 2798 विद्यार्थियों को सीधे नौकरी मिल गई अपने अपने कॉलेज से। दिसंबर महीने तक 530 faculties के 1581 शोधपत्र प्रकाशित हुए ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है क्योंकि रिसर्च जैसे–जैसे बढ़ रही है हमारे जो higher education की facultites हैं वो अपना उनका name fame बढ़ रहा है और उनके शोधपत्र प्रकाशित हो रहे हैं उनके citation बढ़ रहे हैं।

अब मैं स्वास्थ्य विभाग के Outcome Budget पर आता हूं। Outcome Budget 2020–21 में 56 कार्यक्रम हेल्थ डिपार्टमेंट में शामिल किए गए थे जिसमें 1616 outcome indicators थे इनमें से 499 important indicators थे। इन 499 में से 402 यानी कि 80 परसेंट on track हैं, 73 off-track हैं और 24 अभी उसमें उनके बारे में रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है इस रिपोर्ट में। महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स में दिसंबर 2020 तक 496 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए गए इसमें लक्ष्य 750 क्लीनिक का था। औसतन प्रत्येक आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक प्रतिदिन 97 रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। 2020–21 के दौरान 9 से 11 महीने की आयु वर्ग के लगभग 182000 बच्चों को पूर्ण टीकाकरण किया गया जबकि लक्ष्य 296000

बच्चों के टीकाकरण का था। आशा कार्यकर्ताओं ने 120000 संस्थागत प्रसव कराए। दिसंबर 2020 तक टीवी से ग्रस्त 59646 रोगियों का उपचार किया गया लॉकडाउन के बीच में भी और कोविड मैनेजमेंट के बीच में भी। दिसंबर 2020 तक औषधि नियंत्रण विभाग ने लगभग 3073 बिक्री कंपनियों का निरीक्षण किया और नियमों का उल्लंघन करने वाले 397 के लाइसेंस निलंबित या रद्द किए।

सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, 29 इंडीकेटर इसमें शामिल थे इसमें प्रोजेक्ट स्कीम शामिल थे जिसमें 187 आउटकम इंडीकेटर्स थे इसमें से 87 इम्पोर्टेंट इंडीकेटर्स थे इसमें से 87 इंडीकेटर्स में से 54 इंडीकेटर्स ऑनट्रैक है यानी कि 62 परसेंट 18 इंडीकेटर्स ऑफट्रैक हैं not available 17 परसेंट की जानकारी अभी इसमें नहीं शामिल हुई है। इसमें इंपोर्टेंट इंडीकेटर्स में 2020–21 में करीब 439000 वरिष्ठ नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई जिसमें 2019–20 में ये संख्या लगभग 467000 थी। 20–21 में 106000 दिव्यांगों को वित्तीय सहायता दी गई जबकि उससे पहले ये 95324 थी। 2020–21 में 1,11,145 परिवारों को एक बार one time financial assistance उपलब्ध कराई गई जिसमे ऐसे लोग जिनके भरण–पोषण करने वाले मुखिया की मृत्यु हो गई थी।

महिला और बाल विकास विभाग ने अध्यक्षा महोदय, 25 कार्यक्रम आउटकम बजट में शामिल किए, उसमें शामिल थे बजट में जिसमें आउटकम बजट में 200 इंडिकेटर्स रखे गए थे उसमें से 151 इंडिकेटर्स, इंपोर्टेंट इंडिकेटर्स मार्क किए थे इनमें से 60 परसेंट यानि कि 90 इंडिकेटर्स ऑन ट्रैक हैं, 45 इंडिकेटर्स ऑफ ट्रैक हैं। इसमें इंपोर्टेंट की स्थिति यह है कि 2020–21 में 2,75,000 विपतिग्रस्त महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी जबकि पिछले साल 2,66,000 महिलाओं को ऐसी वित्तीय सहायता दी गयी थी। लाडली योजना में विभाग ने 2020 तक नए नामांकन जन्म और विद्यालय स्तर के लिए 3,33,241 आवेदन प्राप्त किए, इसका लक्ष्य 65,000 था लेकिन स्कूल न खुलने की वजह से और एंरोलमेंट का क्योंकि नर्सरी और के.जी. में एडमिशन नहीं हो पाए उस वजह से ये अभी लक्ष्य इस साल हासिल किया जाएगा, लगभग 3,304 का नामांकन दिसम्बर तक किया गया था। लगभग 13 लाख बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं, माताओं को आईसीडीएस

के तहत 10,755 आगंनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवा और प्रिस्कूल की सुविधाएं दी गयीं।

परिवहन विभाग अध्यक्षा महोदय, आउटकम बजट में पिछले बजट में 24 प्रोजेक्ट शामिल किए गए थे, स्कीम शामिल थीं उसमें से 248 आउटकम इंडिकेटर्स थे इनमें से 34 महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स थे इन 34 में से 24 पर ऑन ट्रैक हैं और 10 यानि 29 परसेंट ऑफ ट्रैक हैं। इंपोर्टेंट इंडिकेटर्स में लॉकडाउन के कारण 31 मार्च 2020 से 18 मई 2020 तक बस सेवाएं निलंबित रहीं। डीडीएमए के दिनांक 18/05/2020 के आदेश द्वारा राज्य के अंदर बसों को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई कि एक फेरे में यात्रियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के कार्य निष्पादन पर इसका काफी असर पड़ा था। कलस्टर बसेज का औसत फ्लीट उपयोग प्रतिशत बढ़कर 98.58 परसेंट हो गया जबकि लक्ष्य 97 परसेंट का था। कलस्टर बसेज का ऑन टाइम परफार्मेंस 50 परसेंट लक्ष्य की तुलना में बढ़कर 69.46 परसेंट हो गया है। डीटीसी बसों का औसत फ्लीट उपयोग प्रतिशत घटकर 73.7 परसेंट पर आ गया जबकि लक्ष्य 90 परसेंट का था। डीटीसी बसों का ऑन टाइम परफार्मेंस प्रतिशत 73 परसेंट के लक्ष्य की तुलना में 68 परसेंट रहा। दिसंबर 2020 तक 47.78 लाख प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए गये जबकि लक्ष्य 75 लाख का रखा गया था ये भी लॉकडाउन और जो कोविड के मैनेजमेंट में स्थितियां बदलीं उनकी वजह से नीचे रहा। परिवहन विभाग ने 7 अगस्त, 2020 को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी अधिसूचित कर दी इसके बाद से 4924 नये इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन दिसंबर तक पंजीकृत किये गये। दिसंबर 2020 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीददारों में से 76 परसेंट को प्रोत्साहन राशि का वितरण कर दिया गया था। 5200 डीटीसी और कलस्टर बसों में दिसंबर 2020 तक सीसीटीवी कैमरे लगा दिये गये थे। घुम्मनहेड़ा और मुंडेला कलां में 2 बस डिपो का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

पीडब्लूडी, अध्यक्षा महोदय, इसमें बजट में 37 प्रोजेक्ट रखे गये थे जिसमें 446 आउटकम इंडीकेटर्स थे इनमें से 52 इंडीकेटर्स इम्पोर्टेंट इंडीकेटर्स माने गये थे। इसमें 38 इंडीकेटर्स पर काम ऑन ट्रैक है यानी 73 परसेंट पर 13 इंडीकेटर्स पर काम स्लो है। महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आम लोगों की सुरक्षा

के लिए सार्वजनिक स्थलों पर 1,32,000 सीसीटीवी लगाये गये जिसका लक्ष्य भी 1,32,000 सीसीटीवी लगवाने का ही रखा गया था। शास्त्री पार्क इंटर सेक्शन और सीलमपुर में फ्लाई ओवर का काम पूरा कर लिया गया है और इसे 19/10/2020 को लोगों के लिए खोल दिया गया। बसई दारापुर में नजफगढ़ नाले के पुल को चौड़ा करने का 65 परसेंट कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा कर दिया गया। वजीराबाद और जगतपुर के बीच 2 ऑफ अंडरपास तथा रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट एक पैदल पारपथ का 56 परसेंट काम पूरा हो चुका है। आश्रम चौक पर अंडर पास के निर्माण का 40 परसेंट काम दिसंबर 2020 तक पूरा कर लिया गया है। दिल्ली में दिसंबर, 2020 तक 7000 हॉट स्पॉट बनाए गये है। 5 फुटओवर ब्रिज निर्माण का काम पूरा हो चुका है और 4 फुटओवर ब्रिज का 90 परसेंट से अधिक काम दिसंबर तक पूरा हो चुका है, ये पीडब्लूडी का था।

दिल्ली जल बोर्ड, बजट में इसके 21 प्रोजेक्ट थे जिनमें से 204 आउटकम इंडीकेटर्स बनाये गये थे 68 इम्पोर्टेंट इंडीकेटर्स थे। इसमें से 42 पर काम ऑनट्रैक है, 19 पर काम ऑफट्रैक रहा। इम्पोर्टेंट इंडीकेटर्स दिसंबर 2020 तक 1571 अनाधिकृत कालोनियों को पानी की पाइप लाइन से जोड़ दिया गया इससे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर टैंकर की संख्या में कमी आई। दिसंबर, 2020 तक अनाधिकृत कालोनियों में से 4773 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई गई। दिसंबर, 2020 तक कुल 2667 किलोमीटर की पुरानी या खराब पाइप लाइन को बदला गया इसमें 3 एमजीडी पानी की बचत होनी शुरु हुई। प्रतिमाह 20 किलो लीटर निशुल्क पानी देने की योजना 2020–21 में जारी रखी गई और लगभग 658000 उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 44 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। दिसम्बर, 2020 तक अनाधिकृत कालोनियों में कुल 2735 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई गई और 602 अनाधिकृत कालोनियों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा गया। दिसम्बर, 2020 तक नियमित अनाधिकृत कालोनियों में कुल 1221 किलोमीटर पुरानी सीवर लाइन बदली गई, दिसम्बर तक का ये आंकड़ा है, अध्यक्षा महोदय,उल्लेखनीय काम है क्योंकि मई तक तो कोई भी कंस्ट्रक्शन और किसी भी तरह के काम पे पाबंदी थी, उसके बाद धीरे–धीरे खुला और उसके बाद भी लेबर का माइग्रेशन और इन सबके बीच भी इतनी उपलब्धि होना अपने आप में उल्लेखनीय है।

विद्युत विभाग, इसमें 15 प्रोजैक्ट शामिल किए गए थे, 108 आउटकम इंडीकेटर्स थे जिनमें 52 महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स थे। इनमें से 39 ओन ट्रैक है, ऑफ ट्रैक 7 है, नोट अवेलेबल अभी 6 हैं जिनपर कुछ काम नहीं हुआ। महत्पवूर्ण संकेतकों की स्थिति ये है, दिसम्बर, 2020 में ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता बढ़कर 99.26 प्रसैंट हो गई। अप्रैल से दिसम्बर, 2020 के दौरान दिल्ली ने 6,314 मेगावाट की पीक डिमांड पूरी की। 2019–20 में AT & C loss 8.66 परसेंट रहा। बिजली विभाग ने 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली शुल्क में शत प्रतिशत की सब्सिडी दी और 201 से 400 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं को 800 रुपए प्रतिमाह तक की सब्सिडी दी गई। इससे 36 लाख 50 हजार घरेलू उपभोक्ताओंको फायदा हुआ, ये संख्या कुल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की करीब 89 परसैंट है। यानि कि 89 परसेंट परिवारों को दिल्ली में subsidized rate पर या मुफ्त बिजली का फायदा मिल रहा है। दिसम्बर, 2020 तक दिल्ली में 185 मेगावाट क्षमता का सौर उर्जा संयंत्र लगाया गया, लक्ष्य 300 मेगावाट का था। इन संयंत्रों से 500 मेगा यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, वार्षिक लक्ष्य 500 मेगा यूनिट का था, यानि कि जितना बिजली का उत्पादन लक्ष्य था सौर ऊर्जा से उतना तो हासिल कर लिया गया, अभी और मेगावाट के संयंत्र लगाए जाने बाकी हैं।

पर्यावरण विभाग, आउटकम बजट में 19 कार्यक्रम शामिल किए गए थे इसमें 132 आउटकम इंडीकेटर थे, 33 इम्पोर्टेंट इंडीकेटर्स थे। इनकी प्रगति में 26 पर ऑनट्रैक है, 5 ऑफट्रैक है, 2 इंडीकेटर्स पे नॉट अवेलेबल है। सभी 26 इम्पोंर्टेंट इंडीकेटर्स में, सभी 26 प्रवेसी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र चल रहे हैं। उद्योग, बिजली संयंत्र, होटल इत्यादि से होने वाले उत्सर्जन के 621 सैंपल्स का दिसम्बर, 2020 तक परीक्षण किया गया, जबकि 2020–21 में 700 नमूनों का परीक्षण का लक्ष्य रखा गया था। 2020 तक बैटरी संचालित टू–व्हीलर के लिए 1747 लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई। दिसम्बर, 2020 तक बैटरी संचालित फोर–व्हीलर के लिए 771 लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई। महात्मा गांधी जलवायु परिवर्तन रोकथाम संस्थान द्वारा 44 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिसम्बर, 2020 तक चलाए गए जिनमें 2768 प्रतिभागी शामिल हुए, जबकि लक्ष्य 3000 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग देने का था।

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट– इसमें 8 कार्यक्रम शामिल किये गये थे। 115 आउटकम इंडीकेटर्स थे, 89 महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स थे। उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट इस प्रकार है– 69 यानि 77 परसेंट पर काम on track है, 14 इंटीकेटर्स यानि 16 परसेंट पर off-track है और 6 यानि 7 परसेंट का नॉट अवेलेबल रिपोर्ट है। महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति ये है कि दिसम्बर, 2020 तक ETF द्वारा 3 लाख पौधे लगाये गये। 2020–21 के दौरान ढ़ाई लाख पौधे का लक्ष्य था यानि कि इससे ज्यादा लगा लिये गये। दिसम्बर, 2020 तक अभयारण्य से बाहर 1 लाख 91 हजार पौधे लगाये गये। 2020–21 के लिए 1 लाख 93 हजार का लक्ष्य रखा गया था। दिसम्बर, 2020 तक 3.88 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किये गये, साढ़े तीन लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था यानि कि जन–भागीदारी भी और बढ़ रही है। शहरी वनों का सृजन और प्रबंधन योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2020 तक 5 शहरवन सृजित किये गये और प्रबंधित किये गये जबकि 5 वनों का ही लक्ष्य रखा गया था।

अध्यक्ष महोदय, ये प्रमुख डिपार्टमेंट और उनके प्रमुख इंटीकेटर्स पर मैंने अपना अभी वक्तव्य रखा और ये जैसा मैंने कहा कि ये अपने आप में बेजोड़ पहल है, बजटीय पहल है जो योजना और कार्यक्रमों की निगरानी की प्रक्रिया को बदल रही है। यह न केवल आम जनता और हमारे विभागों के लिए एक सेल्फ–असेसमेंट उपकरण है बल्कि ये शोधकर्ताओं के लिए और विभिन्न विभागों के कामकाज और उसके कार्यक्रमों का अध्ययन करने का एक ऐसा दस्तावेज भी है जिसका देशभर के राज्यों द्वारा अनुकरण किया जा सकता है। आउटकम बजट के संदर्भ में विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा की एक पहल है जो सरकार का एक अतुलनीय और साहसिक कदम है जो वर्ष के अंत में मात्रात्मक और पारदर्शी तरीके से किये गये कार्य का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। विभाग अब अधिक सक्रिय हैं इसकी वजह से और अधिक लक्ष्य उन्मुख होकर दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं जिसके बेहतर परिणाम हासिल हो रहे हैं। आउटकम बजट अब हमारी शासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गया है और सरकार को उसके प्रदर्शन के आधार पर सभी विभागों को रैंकिंग करने में हमें मदद मिलती हैं।

आउटकम बजट 2021–22 को तैयार करने की कवायद अगला जो बजट आएगा, जिसको कल पेश किया जाएगा, उसका आउटकम बजट तैयार करने की कवायद विभाग द्वारा पहले ही शुरू कर दी गई है और आउटकम बजट की एक–एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को मई, 2021 तक उपलब्ध करा दी जाएगी और इसे योजना विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। यह अपनी नियमित निगरानी के लिए 2021–22 के लिए विभिन्न संकेतकों के लक्ष्य में 2020–21 की उपलब्धियां भी पेश करेगा। बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षा : विशेष उल्लेख, नियम 280, माननीय सदस्यगण विशेष उल्लेख, नियम 280 के तहत उठाये जाने वाले मामलों के लिए कुल 7 नोटिस प्राप्त हुए, इन सभी मामलों को पढ़ा हुआ माना जाए।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : माननीय अध्यक्षा जी, भारत सरकार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1956 में एस सी/एस टी, ओ बी सी व समाज के गरीब लोगों के लिए रिहायशी कॉलोनी का निर्माण एम सी डी कॉलोनी, आजादपुर में किया गया था जो भारत सरकार के लोन के अंतर्गत बनाया गया था जिसमें इस कॉलोनी के आवंटियों को मालिकाना हक देने की बात की गई थी। परंतु अब बीजेपी शासित भ्रष्ट एम सी डी की नीयत खराब हो चुकी है और जो मकान इन कालोनी– वासियों को दिए गए थे अब बीजेपी शासित भ्रष्ट एम सी डी ये पूरी कॉलोनी पूंजीपतियों को देने की तैयारी में लगी हुई है। ऐसे क्या कारण हैं कि जनता को यहां से निकालकर प्राईवेट बिल्डरों को ये कॉलोनी की जमीन औने–पौने दामों पर देने की तैयारी हो रही है और कॉलोनीवासियों से खाली कराने की तैयारी चल रही है? जबकि वास्तविक तौर पर यह जमीन एम सी डी की है ही नहीं। अतः महोदय मेरा सदन से अनुरोध है कि उपरोक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर कॉलोनीवासियों को घर से बेघर होने से बचाने की कृपा करें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जल विभाग के माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र विश्वासनगर विधान सभा

क्षेत्र में पेय जल की भीषण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में गाजीपुर गॉव, सैनी एन्क्लेव, कड़कड़डूमा गॉव तथा कड़कड़डूमा कॉलोनी के अंदर पेय जल की भयंकर समस्या है, जहॉ पेय जल की आपूर्ति न के बराबर है और जो पानी आता भी है वह बहुत ही गंदा पानी आता है। जहॉ लोग कम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं गंदे पानी की आपूर्ति होने से लोग जल–जनित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि पेय जल की इस समस्या को ठीक करने के लिए पाईप लाईन को बदला जाए और पर्याप्त मात्रा में पेय जल की आपूर्ति की जाए।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस : अध्यक्ष महोदया, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, सभी सदस्यों व दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं देती हूं जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से मुकाबला किया और जीत हासिल की। मैं आज इस सदन के सामने अपने क्षेत्र की सालों से चलती आ रही समस्याओं पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आर.के.पुरम में तीन क्लस्टर – आदर्श बस्ती–मोहम्मदपुर, लाल बहादुर शास्त्री कैंप एवं मलाई मंदिर कैंप के शौचालयों में पिछले करीब दो सालों से बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं। ऐसे में बस्ती के बच्चों एवं महिलाओं के लिए अंधेरे में शौचालय का प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है। बिजली न आने के कारण पानी की मोटर भी नहीं चलती, जिसके चलते समय अनुसार सफाई भी नहीं होती और गंदगी से स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। बिजली और DUSIB दोनों आप ही के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप दोनों विभागों से ऐसा आपसी निष्कर्ष निकालने का निर्देश दें जिससे बस्ती वालों की दिक्कतों का समाधान हो। शौचालयों का मुआयना करने पर पता चला कि महिलाओं के शौचालय में एक डस्टबिन है जबकि प्रत्येक क्यूबिकल में एक एक डस्टबिन होनी चाहिए ताकि महिलाएं व बच्चियां सैनिटरी–नैपकिन इधर उधर न फेंके। DUSIB का कहना है कि ये नीतिगत बात है। आपसे ये निवेदन है कि कृपया इस पर भी गौर किया जाए।

द्वितीय, आर के पुरम में पिछले कई वर्ष से बेनिटो हुआरेज मार्ग पर सत्य निकेतन कॉलोनी के पास अंडरपास का कार्य चल रहा है। जिससे स्थानीय निवासियों

को ख़ास दिक्कतें आ रही हैं। यह कार्य कब खत्म होगा ये सूचित करें।

इसके अलावा मैं सदन के माध्यम से ये भी जानना चाहती हूं कि मेरे विधायक निधि से पिछले पांच सालों में जितने भी काम SDMC को सौंपे गए हैं, वो पूरे क्यों नहीं हुए व वो कब तक पूरे होंगे?

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि SDMC आर.के.पुरम के PWD रोड के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने की अनुमति क्यूं दे रही है? जितने भी ग्रीन बेल्ट पर टॉवर लगे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। BSES ने उनको किस आधार पर बिजली के कनेक्शन दिए, ये बताया जाए।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र करावल नगर की पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्र की है। यहॉ पर ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण लोग खेती बाड़ी करते थे। परंतु बाद में वहॉ सभी क्षेत्रों में कालोनियॉ बस गई। कालोनियॉ बसने की वजह से खेती बाड़ी के लिये जमीनें खत्म होती गई । इससे पहले जब वहां पर कृषि होती थी तो कृषि की सिंचाई हेतु वहां बिजली के खम्बे तार सहित गड़े हुये थे। कालोनियॉ बसने की वजह से अब वहां खेती बाड़ी नहीं हो रही है और वहॉ बिजली के खम्बे अभी भी तार सहित जीर्णशीर्ण अवस्था में अव्यस्थित तरीके से गड़े हुये हैं जिनमें 11000 किलो वॉट का करंट का प्रवाह बना रहता है, जिनसे कभी भी दुर्घटना घट सकती है और जान–माल के नुकासान होने का खतरा हमेशा बना रहता है।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन और शहरी विकास विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूॅ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र से इन बिजली के खम्भों को तार सहित, जिनकी अब उपयोगिता नहीं है उनको अविलम्ब हटाया जाए।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान शास्त्री पार्क, बुलन्द मस्जिद पर बन रही सरकारी डिस्पैंसरी की ओर दिलाना चाहता हूं। यह डिस्पैंसरी अल्पसंख्यक विभाग, केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के संयुक्त रूप से लोक

निर्माण विभाग के द्वारा बनायी जा रही है। विगत डेढ़–दो वर्षों से इस डिस्पैंसरी का निर्माण कार्य रूका हुआ है। यह बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता की समस्या और उनके हितों को देखते हुए इस डिस्पैंसरी का निर्माण कार्य तुरंत शुरू करवाया जाए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो सके।

श्री अजय कुमार महावर : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र घौण्डा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत गामड़ी घौण्डा मार्ग के चौड़ीकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस मार्ग पर पहले बड़ी–बड़ी बसें चलती थीं, लेकिन धीरे–धीरे यह मार्ग संकरा हो गया है। मास्टर प्लान के हिसाब से इस रोड की चौड़ाई 100 फीट है। इस विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायकों ने भी इस मामले को सरकार के समक्ष उठाया था। वर्ष 2012 में दिल्ली नगर निगम द्वारा इसका डिमार्केशन भी किया गया था। इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से भी मिल चुका हूँ। इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए क्षेत्र के कुछ लोग न्यायालय में भी गये थे और माननीय न्यायालय ने भी सड़क चौड़ा करने के पक्ष में फैसला दिया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि जनहित में इस सड़क के चौड़ीकरण के मार्ग में जो भी बाधायें हैं , उसको दूर कर इस सड़क को जल्द से जल्द चौड़ा करवाया जाए।

श्री अभय वर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मीनगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा विकास मार्ग का सौन्दर्यीकरण का काम करवाया जा रहा है। अक्टूबर, 2020 के बाद से इस सड़क का निर्माण कार्य बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, जिससे वहॉ के निवासियों और व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आदेश देकर इस सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करवायें। इस

सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे खड़े हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूँ कि इस सड़क का सौन्दर्यीकरण करते समय इन बिजली के खंभों को हटाकर बिजली के तारों को भूमिगत करवाया जाए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षाः बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। बोलिए–बोलिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षाः आप बोलिए।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः हमारी मांग ये थी इनके साथ कि जो ये DTC के हमारे मंत्री... जो हमारे माननीय DTC के जो चेयरमैन भी हैं और माननीय मंत्री जी हैं तो जो इनको रखना चाहिए, इन्होंने आज तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया। क्या कारण हैं? क्या जेवीएम कम्पनी से इनका इंट्रस्ट है? और 2 हजार 2 सौ करोड़, सॉरी, 2 सौ करोड़ रूपये का खुलेआम घोटाला है इसका। इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए। ये हमारी आपसे...

माननीय अध्यक्षाः चर्चा के लिए आपकी तरफ से किसी भी प्रकार का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। आपने जब ये बात उठाई, मैंने अपने विभाग में पता किया, आप लोगों की तरफ से इस पर चर्चा के लिए किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया है,। अगर आप इस पर चर्चा चाहते हैं तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि नोटिस दें, नोटिस ऐक्सेप्ट होने के बाद इस पर चर्चा कराई जाएगी।

...व्यवधान...

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर नोटिस की जरूरत नहीं होती है...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षाः अब सदन की कार्यवाही 9 मार्च, 2021 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही 9 मार्च, 2021 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, स्मैट फॉर्म्स, नई दिल्ली–110 007 द्वारा मुद्रित।